Result Mitra
दैनिक जागरण
The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE
दैनिक भास्कर
THE HINDU
जनसत्ता
Daily
CURRENT
AFFAIRS
IAS/PCS
अब होगी करंट अफेयर्स की राह आसान
05 April 2025

विभिन्न देशों में डिफेन्स अटैची की तैनाती

Result Mitra

विभिन्न देशों में डिफेन्स अटैची की तैनाती

संदर्भ

भारत प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक संबंधों का विस्तार करने के अपने लक्ष्य के अनुरूप पहली बार मोज़ाम्बिक, इथियोपिया, आइवरी कोस्ट, फिलीपींस, पोलैंड व आर्मेनिया सहित कई देशों में डिफेन्स अटैची (रक्षा प्रतिनिधि) तैनात करेगा।

Result Mitra

विभिन्न देशों में डिफेन्स अटैची की तैनाती

डिफेन्स अटैची (Defence Attache)

- ये सशस्त्र बलों के सदस्य होते हैं जो विदेश में अपने देश की रक्षा प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि के रूप में दूतावास में कार्य करते हैं।
- डिफेन्स अटैची शब्द सशस्त्र सेवाओं की सभी शाखाओं के कर्मियों को कवर करता है। हालाँकि, कुछ बड़े देश वायु सेना या नौसेना अटैची जैसे व्यक्तिगत सेवा शाखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको नियुक्त कर सकते हैं।

Result Mitra

विभिन्न देशों में डिफेन्स अटैची की तैनाती

- इनका कार्य नियुक्ति वाले राष्ट्र में अपने देश के रक्षा हितों की सुरक्षा करने, उसका विकास करने एवं उसे बढ़ावा देने के साथ ही द्विपक्षीय सैन्य व रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना है।
- कुछ डिफेन्स अटैची को प्रवासन जैसे विशिष्ट मुद्दों पर काम करने के लिए तैनात किया जाता है। ये नाटो, यूरोपीय संघ या संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों के साथ एक सैन्य मिशन के हिस्से के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

Result Mitra

विभिन्न देशों में डिफेन्स अटैची की तैनाती

हालिया घटनाक्रम

- भारत अफ्रीकी राष्ट्र जिबूती में भी एक नया डिफेन्स अटैची नियुक्त करेगा।

जिबूती, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी के आसपास समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह सैन्य ठिकानों के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थल माना जाता है।

Result Mitra

विभिन्न देशों में डिफेन्स अटैची की तैनाती

- भारत, अपने लंदन उच्चायोग एवं मॉस्को दूतावास के सैन्य अधिकारियों वाली अपनी टीमों की ताकत को तर्कसंगत बनाने की भी योजना बना रहा है।

Result Mitra

विभिन्न देशों में डिफेन्स अटैची की तैनाती

डिफेन्स अटैची नियुक्ति की आवश्यकता

- चीन द्वारा पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, सेशेल्स व संयुक्त अरब अमीरात में संभावित ठिकानों के अतिरिक्त विदेशी सैन्य प्रतिष्ठानों की स्थापना संबंधी निरंतर समझौतों का मुकाबला करना।

Result Mitra

विभिन्न देशों में डिफेन्स अटैची की तैनाती

- चीन द्वारा क्यूबा, इक्वेटोरियल गिनी, ताजिकिस्तान व तंजानिया में सैन्य सुविधाएँ स्थापित करने की भी संभावना है।
- चीन ने जिबूती में केवल एक विदेशी सैन्य सुविधा की पुष्टि की है।
- वर्ष 2017 से चालू चीन की जिबूती सुविधा की पहुँच महत्वपूर्ण लाल सागर शिपिंग लेन तक है।

Result Mitra

विभिन्न देशों में डिफेन्स अटैची की तैनाती

अफ्रीकी क्षेत्र पर विशेष बल

- दुनिया भर के प्रमुख क्षेत्रों में अपनी सैन्य कूटनीति को मजबूत करने और तर्कसंगत बनाने में भारत के लिए अफ्रीका एक फोकस क्षेत्र है।

Result Mitra

विभिन्न देशों में डिफेन्स अटैची की तैनाती

- अफ्रीका में भारत की सैन्य कूटनीति को बढ़ाने का निर्णय व्यापार एवं निवेश से लेकर शिक्षा व रक्षा तक के क्षेत्रों में अफ्रीकी देशों के साथ देश की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों से मेल खाता है।
- दुनिया भर में 26 नए मिशन स्थापित करने की विदेश मंत्रालय की योजना के तहत 18 मिशन अफ्रीकी देशों में स्थापित किए जा रहे हैं।

Result Mitra

विभिन्न देशों में डिफेन्स अटैची की तैनाती

- भारत ने विगत वर्ष नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को जी-20 का सदस्य बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- इससे सैन्य सहयोग एवं हथियारों की बिक्री की संभावनाएँ भी खुलेंगी क्योंकि कई अफ्रीकी देश अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

Result Mitra

विभिन्न देशों में डिफेन्स अटैची की तैनाती

अन्य देशों में नियुक्ति

फिलीपींस व आर्मेनिया में पहली बार डिफेन्स अटैची तैनात करने का निर्णय भारत द्वारा दोनों देशों को हथियार प्रणालियों की बिक्री के बाद उठाया गया है।

- वर्ष 2022 में फिलीपींस ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए लगभग 375 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए।

Result Mitra

विभिन्न देशों में डिफेन्स अटैची की तैनाती

- भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट लॉन्चर का पहला विदेशी ग्राहक वर्ष 2022 में 1 आर्मेनिया बना।

UPSC Mains GS Paper 3

प्रश्न 1 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. डिफेन्स अटैची केवल थल सेना से नियुक्त किए जाते हैं।

2. भारत ने पहली बार जिबूती और आर्मेनिया में डिफेन्स अटैची तैनात करने का निर्णय लिया है।

3. डिफेन्स अटैची का एक प्रमुख कार्य द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना होता है।

उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 2 और 3

B. केवल 3

C. केवल 1 और 2

D. सभी 1, 2 और 3

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित हत्याओं से संबंधित मुद्दे

Result Mitra

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित हत्याओं से संबंधित मुद्दे

संदर्भ

वर्तमान में पाकिस्तान एवं कनाडा द्वारा भारत पर उनके देशों में लक्षित हत्याओं (Target Killings) का आरोप लगाया है। हालाँकि, भारत के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि लक्षित हत्याएँ भारत की नीति नहीं है।

Result Mitra

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित हत्याओं से संबंधित मुद्दे

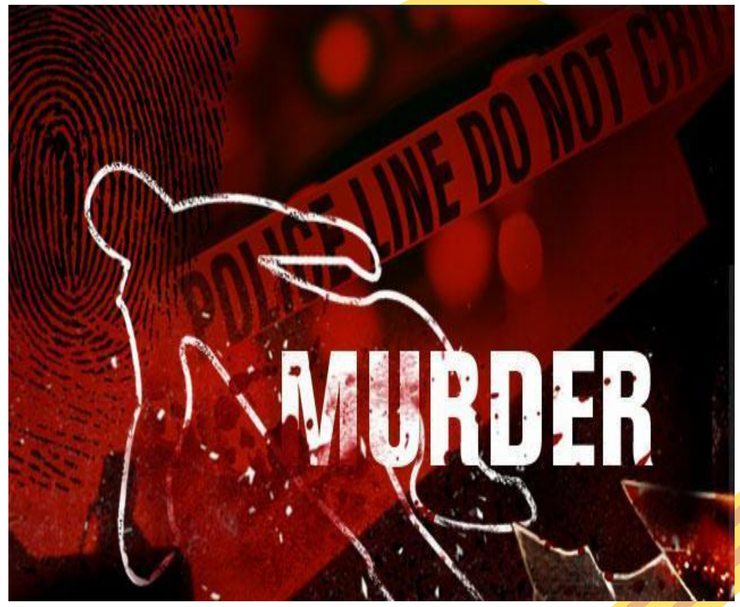

विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया

पाकिस्तान

• पाकिस्तान अपने देश में 2 लोगों की हत्या का आरोप भारत पर लगा चुका है।

उसका तर्क है कि पाकिस्तान के भीतर मनमाने ढंग से नागरिकों को 'आतंकवादी' घोषित कर न्यायोत्तर दंड देने की भारत की तैयारी का दावा स्पष्ट रूप से उसके दोषी होने की स्वीकारोक्ति है।

Result Mitra

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित हत्याओं से संबंधित मुद्दे

अमेरिका

- अमेरिका ने पाकिस्तान के दावे के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। हालाँकि, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्या पाकिस्तान के दावों का प्रयोग अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा किया जाएगा।

Result Mitra

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित हत्याओं से संबंधित मुद्दे

- अमेरिकी खुफिया विभाग (FBI) का दावा है कि वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारियों ने न्यूयॉर्क में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत पन्नू पर हमले का षड्यंत्र रचा था।

Result Mitra

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित हत्याओं से संबंधित मुद्दे

कनाडा

कनाडा एक खालिस्तानी अलगाववादी नेता की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता की जाँच कर रहा है। हालाँकि, इस संदर्भ में वह अभी तक भारत सरकार के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है।

Result Mitra

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित हत्याओं से संबंधित मुद्दे

अंतर्राष्ट्रीय विनियमन

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार (Human Rights) कानून

- प्रत्येक नागरिक को जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
- इसे मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा से शक्ति मिलती है।

Result Mitra

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित हत्याओं से संबंधित मुद्दे

अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी (Humanitarian) कानून

- यह सशस्त्र संघर्ष के दौरान गैर-लड़ाकों (असैनिक या सिविलियन) की रक्षा के सिद्धांतों को निर्धारित करता है।
- इसके अनुसार, गैर-लड़ाकों की रक्षा की जानी चाहिए क्योंकि युद्ध या आत्मरक्षा अभियानों के दौरान भी राज्यों के कुछ दायित्व हैं।

Result Mitra

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित हत्याओं से संबंधित मुद्दे

संयुक्त राष्ट्र चार्टर

• शांति के लिए खतरा, शांति का उल्लंघन और आक्रमकता के कृत्यों के संबंध में कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर VII के अनुच्छेद 51 में प्रावधान किया गया है।

इसके अनुसार, यदि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमला होता है तो व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार में कोई बाधा नहीं आती है।

Result Mitra

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित हत्याओं से संबंधित मुद्दे

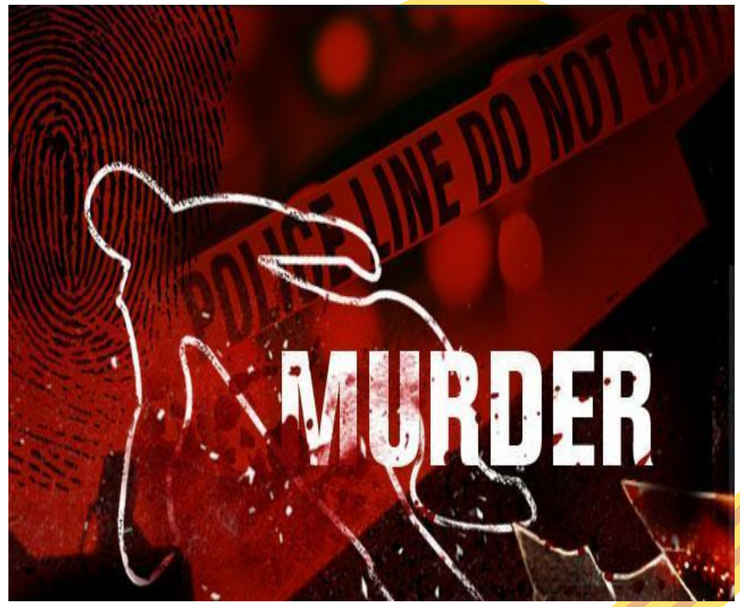

दोहरा रवैया

- वर्तमान में वैश्विक स्तर पर दोहरे मापदंड विद्यमान हैं क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका ने विभिन्न देशों में ड्रोन हमलों के माध्यम से लक्षित हत्याएँ की हैं।

Result Mitra

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित हत्याओं से संबंधित मुद्दे

- इसे अमेरिका ने आत्मरक्षा की प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमति दी गई है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुसार, देशों के पास आत्मरक्षा का व्यक्तिगत अधिकार है।

Result Mitra

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित हत्याओं से संबंधित मुद्दे

निष्कर्ष

- इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैश्विक शक्तियाँ अपने लिए और भारत जैसे अन्य देशों के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित करती हैं। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत के पास उन परिणामों से निपटने के लिए कूटनीतिक क्षमता है।

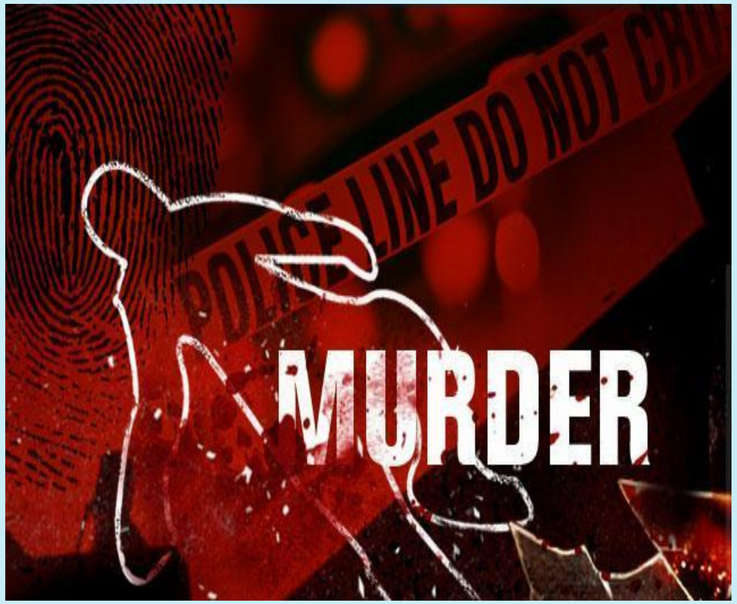

UPSC Mains GS Paper 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लक्षित हत्याएँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन कर सकती हैं।

2. अमेरिका ने 9/11 के बाद ड्रोन हमलों के माध्यम से कई लक्षित हत्याएँ की हैं।

3. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी देश आत्मरक्षा के नाम पर किसी अन्य देश में सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता।

उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. सभी 1, 2 और 3

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

संदर्भ

• भारत, बिहार के रक्सौल से नेपाल के काठमांडू तक 141 किमी. लंबी रेलवे लाइन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। यह रेलवे लाइन भारत के रेल नेटवर्क को शेष दक्षिण एशिया से जोड़ने की एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है।

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

• दूसरी ओर, तिब्बत के केरुंग से नेपाल के काठमांडू के बीच 75 किमी. लंबी रेलवे लाइन बनाने की योजना पर चीन काम कर रहा है। यह लाइन चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है।

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

भारत-नेपाल रेल संपर्क की पृष्ठभूमि

- नेपाल में सबसे पहले रेलवे लाइन अंग्रेजों ने वर्ष 1927 में रक्सौल को अमलेखगंज (नेपाल) से जोड़ने के लिए बनाई थी। यह नेपाल में पहली नैरो गेज रेलवे लाइन थी।

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

• एक दशक बाद वर्ष 1937 में अंग्रेजों ने बिहार के जयनगर से नेपाल के धार्मिक केंद्र जनकपुर को जोड़ने के लिए जनकपुर-जयनगर नामक दूसरी नैरो गेज रेलवे लाइन विकसित की थी।

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

• नवीनतम विकास क्रम में रक्सौल से काठमांडू के बीच रेलवे लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार किया जा चुका है।

• नेपाल एवं चीन द्वारा वर्ष 2017 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों ने 21 जून, 2018 को केरुंग-काठमांडू रेलवे के निर्माण के लिए सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी के संदर्भ में भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

• प्रारंभ में जब नेपाल एवं चीन ट्रांस-हिमालयी रेलवे परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के लिए नियमित संपर्क में थे तब भारत अधिक सक्रिय नहीं रहा। किंतु, बाद में चीन के कदम का मुकाबला करने के लिए रक्सौल एवं काठमांडू के बीच रेलवे लाइन के निर्माण में भारत अधिक सक्रिय हो गया। इस परियोजना की कुल निवेश लागत 4,000 करोड़ रुपए अनुमानित है।

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

- केरुंग-काठमांडू रेलवे के निर्माण पर बातचीत रक्सौल-काठमांडू परियोजना से बहुत पहले शुरू हुई थी। हालाँकि, भारत ने रक्सौल-काठमांडू रेलवे लाइन के लिए DPR तैयार करने में कम-से-कम शुरुआती चरण में चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने रक्सौल-काठमांडू लाइन के लिए DPR पहले ही पूर्ण कर ली है; जबकि चीन अभी शुरुआती चरण में है।

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

• नेपाल के कई विशेषज्ञों का मानना है कि केरुंग एवं काठमांडू के बीच ट्रांस-हिमालयी रेलवे का निर्माण तकनीकी व वित्तीय आधार पर चुनौतीपूर्ण है। कठिन भू-भाग और इस क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता इस परियोजना को मूर्त रूप देने में बाधक है। रेल नेटवर्क के नेपाल खंड के 95% हिस्से में सुरंग बनाने की जरूरत है, जिसकी लागत देश को लगभग 3-3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है।

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

- अधिकांश विशेषज्ञों का सुझाव है कि नेपाल को केरुंग से काठमांडू के बीच रेलवे कनेक्टिविटी की बजाय सड़क कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता के भू-राजनीतिक निहितार्थ

- तिब्बत एवं काठमांडू को रेलवे से जोड़ने वाली चीन की परिकल्पना हिमालय के चुनौतीपूर्ण इलाके के कारण एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम है। यह परियोजना चीन को हिंद महासागर के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान कर सकती है और चीन के प्रभाव को बढ़ा सकती है।

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

इसके अतिरिक्त यह चीन के साथ नेपाल की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, नए आर्थिक अवसर खोलेगा और लोगों-से-लोगों के मध्य आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाएगा।

• विगत कई दशकों से भारत ने रेलवे क्षेत्र सहित बुनियादी ढाँचागत 1 परियोजनाओं के विकास के लिए नेपाल को अत्यधिक सहयोग दिया है। रेलवे के क्षेत्र में भारत-नेपाल

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

सहयोग का इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना है। नेपाल के साथ रेल कनेक्टिविटी सुधारने को लेकर भारत सक्रिय रूप से कार्यरत है।

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

• बिहार एवं नेपाल के बीच यात्री रेल सेवा ने सीमा पार गतिशीलता को बढ़ाया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार व पर्यटन सुविधाजनक बन गया है। आगे के विकास व विस्तार के साथ एक इंटर-कनेक्टेड रेलवे नेटवर्क संभावित रूप से भारत से नेपाल होते हुए चीन सीमा तक भी पहुँच सकता है। इस तरह की कनेक्टिविटी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगी।

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

चुनौतियाँ

- भारत एवं नेपाल के बीच रेल संपर्क का निर्माण एक जटिल व चुनौतीपूर्ण परियोजना है। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्य कठिन है और निर्माण लागत अधिक होने की संभावना है।

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

- जटिल भू-भाग, पर्यावरण संबंधी चिंताएँ और महत्त्वपूर्ण निवेश आवश्यकता जैसी चुनौतियाँ इन परियोजनाओं की प्राप्ति में बाधाएँ पैदा करती हैं।
- इसके अतिरिक्त, ऐतिहासिक तनाव एवं रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता सहित क्षेत्र की भू-राजनीतिक गतिशीलता, रेलवे कनेक्टिविटी पहल की प्रगति व परिणामों को प्रभावित कर सकती है।

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

संभावित लाभ

• रेल संपर्क के निर्माण से लोगों के लिए और सामानों के लिए भारत व नेपाल के बीच यात्रा करना आसान हो सकता है और इससे नेपाल के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल सकता है।

Result Mitra

नेपाल में रेल कनेक्टिविटी और भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

- भारत, चीन व नेपाल के बीच रेल संपर्क में आर्थिक विकास, व्यापार सुविधा एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा और परिवहन लागत कम होगी, जिससे तीनों देशों को लाभ होगा।

UPSC Mains GS Paper 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चीन की केरुंग-काठमांडू रेल परियोजना भारत की रक्सौल-काठमांडू परियोजना से पहले शुरू हुई थी।

2. भारत ने अपनी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पहले ही पूरी कर ली है।

3. नेपाल के रेल नेटवर्क का अधिकांश हिस्सा समतल भूभाग में स्थित है, जिससे लागत कम हो जाती है।

उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. सभी 1, 2 और 3

यूरोपीय संघ का AI अधिनियम एवं ब्रुसेल्स प्रभाव

Result Mitra

यूरोपीय संघ का AI अधिनियम एवं ब्रुसेल्स प्रभाव

संदर्भ

यूरोपीय संघ (EU) ब्रुसेल्स प्रभाव (Brussels Effect) के रूप में ज्ञात एक घटना के माध्यम से वैश्विक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

Result Mitra

यूरोपीय संघ का AI अधिनियम एवं ब्रुसेल्स प्रभाव

क्या है ब्रुसेल्स प्रभाव

• ब्रुसेल्स प्रभाव एक नियामक शक्ति (Regulatory Power) के रूप में यूरोपीय संघ की स्थिति को संदर्भित करता है। यह अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं वैश्विक शासन के पारंपरिक तरीकों को दरकिनार करते हुए अपने स्वयं के नियामक ढाँचे के माध्यम से वैश्विक मानकों को आकार देने की यूरोपीय संघ की क्षमता को परिभाषित करता है।

Result Mitra

यूरोपीय संघ का AI अधिनियम एवं ब्रुसेल्स प्रभाव

- यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है।
- यूरोपीय संघ अपने विशाल आंतरिक बाज़ार के लिए उच्चस्तरीय मानक स्थापित करता है। यह बहुराष्ट्रीय निगमों को उनके वैश्विक परिचालन में इन नियमों का पालन करने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान करता है।

Result Mitra

यूरोपीय संघ का AI अधिनियम एवं ब्रुसेल्स प्रभाव

- बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने पूरे व्यवसाय में मानकों के एक ही सेट का पालन करने से सुव्यवस्थित होने के साथ ही प्रशासनिक बोझ कम होता है।
- निगमों द्वारा इसे अपनाने से वैश्विक वाणिज्य व्यवस्था का क्रमिक यूरोपीयकरण (Europeanisation) होता है, जो डाटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, उत्पाद सुरक्षा, वित्तीय सेवाओं, बौद्धिक संपदा, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

Result Mitra

यूरोपीय संघ का AI अधिनियम एवं ब्रुसेल्स प्रभाव

• ब्रुसेल्स प्रभाव सूक्ष्मता से संचालित होता है, जो भू-राजनीतिक एवं आर्थिक दबाव के बजाय बाज़ार की ताकतों पर निर्भर करता है। यह प्रभाव 21वीं सदी में सॉफ्ट पावर के एक नए रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ यूरोपीय संघ का प्रभाव उसके नियमों के आकर्षण एवं प्रभावशीलता से उत्पन्न होता है।

Result Mitra

यूरोपीय संघ का AI अधिनियम एवं ब्रुसेल्स प्रभाव

यूरोपीय संघ का ए.आई. अधिनियम और ब्रुसेल्स प्रभाव की अभिव्यक्ति

ए.आई. अधिनियम

- यूरोपीय संसद द्वारा पारित ए.आई. अधिनियम का उद्देश्य ए.आई. अनुप्रयोगों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले नियम स्थापित करना है।

Result Mitra

यूरोपीय संघ का AI अधिनियम एवं ब्रुसेल्स प्रभाव

• यह ए.आई. के तीव्र विकास एवं परिनियोजन (Deployment) की सीधी प्रतिक्रिया है, जिसने दुनिया भर की सरकारों को संभावित नुकसानों को दूर करने के उपाय खोजने के लिए प्रेरित किया है।

• ब्रुसेल्स प्रभाव के मूलभूत सिद्धांतों पर बल देते हुए ई.यू. का कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम (AI Act) अपनी व्यापकता, कानूनी महत्त्व एवं यूरोपीय उपभोक्ता बाज़ार के आकार के कारण मज़बूत स्थिति में है।

Result Mitra

यूरोपीय संघ का AI अधिनियम एवं ब्रुसेल्स प्रभाव

- यह ए.आई. के विकास एवं परिनियोजन के भविष्य को आकार देने में इसके महत्त्व को रेखांकित करता है।
- फेस रिकग्निशन, बायोमेट्रिक डाटा संग्रह, वृहत भाषा मॉडल, प्रशिक्षण डाटा एवं परीक्षण आवश्यकताओं जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए ए.आई. अधिनियम एक व्यापक दायरे व अधिदेश का दावा करता है।

Result Mitra

यूरोपीय संघ का AI अधिनियम एवं ब्रुसेल्स प्रभाव

ब्रुसेल्स प्रभाव की अभिव्यक्ति के रूप में

- यूरोपीय संघ ए.आई. अधिनियम को ब्रुसेल्स प्रभाव की एक अन्य अभिव्यक्ति के रूप में देखता है।
- ब्रुसेल्स प्रभाव से ए.आई. अधिनियम के संबंधित राजनीतिक, सुरक्षात्मक, आर्थिक व सामाजिक जोखिमों को कम करने के लिए ए.आई. विनियमन की जटिलताओं को दूर करने वाले अन्य देशों के लिए एक ब्लूप्रिंट एवं मॉडल के रूप में कार्य करने की संभावना है।

UPSC Mains GS Paper 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ब्रुसेल्स प्रभाव यूरोपीय संघ की सैन्य शक्ति को दर्शाता है।

2. यूरोपीय संघ का AI अधिनियम वैश्विक AI विनियमन के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है।

3. ब्रुसेल्स प्रभाव बाज़ार की ताकतों पर आधारित एक सॉफ्ट पावर रणनीति है।

उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 2

D. सभी 1, 2 और 3

संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता

Result Mitra

संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य का दर्जा देने के लिए अल्जीरिया द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो कर दिया।

Result Mitra

संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता

फिलिस्तीन की वर्तमान स्थिति

- यह प्रस्ताव वर्ष 1947 के वादे को पूर्ण करने के प्रयास में एक कदम था।
- इस वादे के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मूलत: तत्कालीन फिलिस्तीन को दो भागों अर्थात् यहूदी एवं अरब में विभाजित करने वाले प्रस्ताव को अपनाया था।

Result Mitra

संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता

- वर्ष 1949 में केवल इजरायल ही संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बना।
- वर्ष 2012 में फिलिस्तीन राज्य को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ। हालाँकि, इसे अभी तक पूर्ण सदस्य की मान्यता नहीं प्राप्त हुई।
- अमेरिका का तर्क है कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र प्रक्रिया के माध्यम से नहीं बल्कि 'पक्षों के मध्य प्रत्यक्ष संवाद' के माध्यम से सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए।

Result Mitra

संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता

संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता की प्रक्रिया

- किसी भी नए सदस्य देश को शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।

Result Mitra

संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता

- संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए कोई भी आवेदन संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास किया जाता है जिसे फिर सुरक्षा परिषद एवं महासभा को भेजा जाता है।
- नए सदस्यों के प्रवेश पर गठित 15 सदस्यीय समिति इस मामले पर विचार-विमर्श के बाद महासभा में प्रवेश के लिए निर्णय लेती है।

Result Mitra

संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता

प्रावधान

• संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता अन्य सभी शांतिप्रिय राज्यों के लिए खुली है जो वर्तमान चार्टर में निहित दायित्वों को स्वीकार करते हैं और इन दायित्वों को पूर्ण करने में सक्षम व इच्छुक हैं।

Result Mitra

संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता

- सुरक्षा परिषद इस प्रस्ताव पर मतदान कर सकती है और इसके पक्ष में कम-से-कम नौ सदस्य होने चाहिए।
- इसके स्थायी सदस्यों, यथा चीन, फ्राँस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका में से यदि कोई भी सदस्य वीटो शक्ति का प्रयोग करता है तो यह प्रस्ताव खारिज हो जाता है।

Result Mitra

संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता

महासभा की भूमिका

- सुरक्षा परिषद् की सिफारिश प्राप्त होने के तुरंत बाद महासभा इस मामले पर मतदान करती है, जिसमें सभी 193 सदस्य देश इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं।
- महासभा को किसी नए सदस्य को स्वीकार करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

Result Mitra

संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता

- एक बार एक प्रस्ताव अपनाए जाने के बाद नए सदस्य को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र में शामिल कर लिया जाता है।

UPSC Mains GS Paper 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए केवल महासभा की स्वीकृति पर्याप्त है।

2. फिलिस्तीन को वर्ष 2012 में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ था।

3. अमेरिका ने फिलिस्तीन की सदस्यता के प्रस्ताव को वीटो कर दिया था।

उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 2 और 3

B. केवल 1 और 3

C. केवल 1 और 2

D. सभी 1, 2 और 3

Thank you !

Result Mitra